

भारत सरकार  
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 1510  
13 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

महाराष्ट्र में शहरी विकास

1510. श्री अरविंद गणपत सावंत:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी विकास के लिए कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में शहरी विकास के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार से जिलेवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ग) शहरी विकास योजनाओं में शामिल महाराष्ट्र के शहरी स्थानीय निकायों की जिलेवार संख्या कितनी है; और

(घ) ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जिसमें महाराष्ट्र के शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया गया है और जिलेवार संभावित विकास कार्य किए जाने हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री  
(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ) : सातवीं और बारहवीं अनुसूचियों के साथ संविधान के अनुच्छेद 243ब के प्रावधानों के अनुसार, शहरी विकास से संबंधित मामले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अपने विभिन्न प्रमुख मिशनों/कार्यक्रमों जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0), स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम), स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0 (एसबीएम-यू 2.0), प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू 2.0) और शहरी परिवहन (यूटी) आदि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके शहरी विकास एजेंडे में कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करता है। इस मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सहायता जिलों या शहरी स्थानीय निकायों को जारी ना करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती है। इसलिए, जिलावार/ शहरी स्थानीय निकाय वार जानकारी केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। इसका विवरण अनुलग्नक में है।

'महाराष्ट्र में शहरी विकास' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1510 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत और अमृत 2.0): -

अमृत के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के लिए 7,759.32 करोड़ रु. की राज्य वार्षिक कार्य योजनाएँ अनुमोदित की जा चुकी हैं। राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 8,013.28 करोड़ रु. की लागत वाली 208 परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिनमें से 7,543.14 करोड़ रु. के कार्य वास्तविक रूप से पूरे हो चुके हैं। इन परियोजनाओं में 4,446.06 करोड़ रु. की लागत वाली 43 जलापूर्ति परियोजनाएँ, 3,294.03 करोड़ रु. की लागत वाली 36 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएँ, 94.06 करोड़ रु. की लागत वाली एक जल निकासी परियोजना और 179.13 करोड़ रु. की लागत वाली 128 हरित स्थल और पार्क परियोजनाएँ शामिल हैं।

अमृत 2.0 के अंतर्गत अब तक इस मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य में 30,553.59 करोड़ रु. की 286 परियोजनाएँ अनुमोदित की जा चुकी हैं, जिनमें 15,831.02 करोड़ रु. की 117 जलापूर्ति परियोजनाएँ, 12,992.75 करोड़ रु. की 48 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएँ, 1,540.49 करोड़ रु. की 96 जलाशय नवीकरण परियोजनाएँ और 189.34 करोड़ रु. की 25 हरित स्थल और पार्क परियोजनाएँ शामिल हैं।

स्वच्छ भारत मिशन – शहरी (एसबीएम-यू और एसबीएम-यू 2.0):

इस मिशन के विभिन्न घटकों के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार से 6907.44 करोड़ रु. की परियोजना लागत वाले कुल पांच प्रस्ताव प्राप्त हुए और इन सभी पांच प्रस्तावों को 2495.40 करोड़ रु. की केन्द्रीय हिस्सेदारी जारी करने के लिए अनुमोदित कर दिया गया है।

स्मार्ट सिटी मिशन:-

इस मिशन के अंतर्गत राज्य से 8 शहरों औरंगाबाद, कल्याण-डोंबिवली, नागपुर, नासिक, पिंपरी-चिंचवाड़, पुणे, सोलापुर और ठाणे का चयन किया गया है। कुल 17,044 करोड़ रु. की लागत वाली 348 परियोजनाओं का कार्य शुरू हो चुका है, जिनमें से 15,146 करोड़ रु. की

लागत से 324 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 1,898 करोड़ रु. की लागत वाली शेष 24 परियोजनाएं कार्यान्वयन के चरण में हैं।

प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई- यू और पीएमएवाई - यू 2.0 ):-

अब तक महाराष्ट्र राज्य के लिए कुल 13.64 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 11.60 लाख आवास निर्माणाधीन हैं और 9.33 लाख आवास पूरे हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इस योजना की अवधि, जो पहले 31.03.2022 तक थी, सभी स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना 31.12.2025 तक बढ़ा दी गई है, लेकिन इस योजना का ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) घटक इस विस्तार में शामिल नहीं है।

शहरी परिवहन (यूटी): -

मेट्रो रेल प्रणाली सहित शहरी परिवहन शहरी विकास का एक अभिन्न अंग है, जो राज्य का विषय है। मेट्रो रेल परियोजनाओं सहित शहरी परिवहन प्रणाली की योजना और विकास का कार्य संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता मांगे जाने पर इन परियोजनाओं की व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर मौजूदा नीति के अनुसार वित्तीय सहायता देने पर विचार करती है।

50:50 संयुक्त उद्यम मॉडल के तहत कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र सरकार से पिछले पांच वर्षों में प्राप्त मेट्रो रेल परियोजनाओं के प्रस्तावों की सूची निम्नानुसार है : -

क्रम. सं.	परियोजना का नाम	लंबाई किलोमीटर में	लागत (₹ करोड़ में)
1	नागपुर मेट्रो रेल परियोजना (चरण-II)	43.80	6,708.00
2	पुणे मेट्रो रेल परियोजना कॉरिडोर 1ए: पिंपरी-चिंचवाड (पीसीएमसी) से निगडी	4.413	910.18
3	ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो परियोजना न्यू ठाणे से न्यू ठाणे (रिंग कॉरिडोर)	29	12,200.10
4	पुणे मेट्रो रेल परियोजना विस्तार लाइन स्वर-गते से कात्रज तक	5.464	2,954.53
5	पुणे मेट्रो रेल परियोजना चरण-2 वनाज से चांदनी चौक और रामवाडी से वाघोली / विठ्ठलवाडी	12.75	3,626.24
6	पुणे मेट्रो रेल परियोजना चरण-2, लाइन-4: खराडी - हडपसर- स्वर-गते- खडकवासला नाल स्टॉप- वारजे - माणिक बाग की स्पर लाइन के साथ	31.63	9897.19

\*\*\*\*\*